(d) The law and order situation is constantly under review and a number of steps including induction of more security forces in sensitive areas, intensified patrolling, laying of 'nakas' and conduct of combing operations to apprehend and flush out terrorists have been taken by the State Government.

(e) No appreciable change is visible in the attitude of terrorists.

देश में साम्प्रदायिक दंगे

321. डा० रत्नाकर पाण्डेय :
श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
श्री शांति त्यागी :
कुमारी सरोज खापर्डे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1990 से बाद की अवधि में देश में भारी पैमाने पर दंगे हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये दंगे किन-किन राज्यों और कस्बों/शहरों में हुये तथा इनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन दंगों में, राज्य-वार कितने-कितने लोग मारे गये और घायल हुये तथा संपत्ति की कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन दंगों का प्रारंभ लगभग एक ही प्रकार से हुआ था ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने भविष्य में इस प्रकार के दंगों से समाज और देश की रक्षा करने के लिये कोई ठोस कार्य योजना तैयार की है, यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के आधार पर 1 अक्तूबर, 1990 से 15 फरवरी, 1991 के बीच देश में हुये बड़े सांप्रदायिक दंगों का विवरण, अनुपत्र में दिया गया है ।

(घ) और (ङ) [देखिये परिशिष्ट 157, अनुपत्र सं० 12] संलग्न विवरण में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

विवरण

देश में साम्प्रदायिक दंगों के संबंध में दिनांक 26 फरवरी, 1991 के लिए पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 321 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में विवरण

देश में हाल में सांप्रदायिक स्थिति में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के कारण कुछ तनाव उत्पन्न हुआ । तथापि, दंगे निश्चित रूप से समाज विरोधी और सांप्रदायिक तथा राष्ट्र विरोधी तत्व का काम है । जब कभी आवश्यकता पड़ती है, अथवा मांग की जाती है तो दंगों से प्रभावकारी ढंग से निपटने और उन्हें काबू करने के लिये राज्य सरकारों को अर्ध-सैनिक बल तथा उपकरण आदि उपलब्ध करा कर उन्हें मदद दी जाती है ।

सांप्रदायवाद की बुराईयों से निपटने के उपायों का पता लगाने की दृष्टि से इस विवादास्पद समस्या का हल ढूंढने के लिये राष्ट्रीय एकता परिषद विचार विमर्श कर रही है । 1990 के दौरान परिषद की दो बैठकें हुई—पहली बैठक अप्रैल में नई दिल्ली में तथा दूसरी बैठक सितम्बर में मद्रास में हुई । इन बैठकों में इस आशय के प्रस्ताव पारित किये गये कि समस्या का हल शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जाय, बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि समस्या का सौहार्दपूर्ण हल निकाला जाय और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाय कि देश में पहले से व्याप्त सांप्रदायिक स्थिति और खराब हो ।

सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता, दोनों पहलुओं को बढ़ावा देने की दृष्टि

से इस समय गृह मंत्रालय में एक योजना चालू है जिसके अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में इस प्रयोजनार्थ उत्सव तथा विचार गोष्ठियां आयोजित करने के लिये स्वयं सेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

देश में सांप्रदायिक सद्भावना और सांप्रदायिक दंगों को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अप्रैल, 1990 में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये थे, जिनमें इस बारे में विस्तृत उपाय बताये गये हैं। भड़काने वाले भाषणों, लेखों आदि जिससे देश में सांप्रदायिक वातावरण खराब होता है, को रोकने के बारे में सुझावों का एक सेट भी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजा गया है।

गृह मंत्रालय भी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये 15 सूत्री कार्यक्रम के कुछ पहलुओं का प्रबोधन कर रहा है। इनमें विशेष न्यायालयों का गठन करना, दंगा पीड़ितों को राहत देना शामिल है।

Migration of Hindu families from Kashmir

322. SHRI KRISHAN LAL SHARMA:
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of Hindu Families and total number of persons who have migrated from Kashmir during 1990 and the current year so far;

(b) the number of those who have been provided reasonably suitable accommodation by Government and by non-Government agencies;

(c) the amount of money spent by the Central Government and Jammu and Kashmir Administration to rehabilitate the migrants, how many have been provided durable rehabilitation; and

(d) the amount of compensation given to them per family/individual?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (d) 54,836 migrant families have been registered at Jammu and 16,095 families have been registered at Delhi About 6,000 families in Jammu and 600 families in Delhi have been accomodated in available Govt. building and tents.

It is the endeavour of the Govt. to enable return of the migrants to their homes in the Valley as soon as the law and order situation improves. Therefore, their permanent rehabilitation outside the Valley has not been contemplated.

On various relief measures for the Kashmir migrants, Govt. of Jammu & Kashmir has spent Rs. 27.09 crores upto 31.12.1990. Delhi Administration has spent Rs. 2,12,95,491/- upto 31.01.91.

Returning of Nuclear submarine INS Chakra to Soviet Union

323. SHRIMATI VEENA VERMA.
SHRI KAPIL VERMA:
SHRIMATI KAILASHPATI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether nuclear propelled submarine INS-Chakra has been returned to the Soviet Union;

(b) if so, when and the reasons for not extending the three year lease;

(c) whether any alternative arrangements have been made; and

(d) whether acquisition of more and higher class nuclear propelled submarines is necessary for the country to play rightful role in the ocean surrounding it particularly in view of latest developments, if so, what is Government's reaction thereto?